U.G. Part-II (Hons.)
Paper-VI
[Under Topic - Economic Policy of the Company.]

COMMERCIALIZATION OF AGRICULTURE

Page No.:
Date:
YOUVA

कृषि का वाणिज्यीकरण : कारण तथा परिणाम

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू 'भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण' था। कृषि के वाणिज्यीकरण का तात्पर्य उत्पादन की ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कृषि उत्पादों का प्रयोग व्यापारिक मुनाफे के लिए किया जा सके। यह एक धीमी विकास की प्रक्रिया थी जिसे पूर्व-औपनिवेशिक काल में भी देखा गया। औपनिवेशिक काल में यह प्रक्रिया अधिक तेज हुई तथा इसकी संरचना में परिवर्तन हुए। मुगल काल में वाणिज्यीकरण के प्रेरित करनेवाले तत्व - राजस्व का दबाव अथवा लगभग 15 प्रतिशत शहरी आबादी के उपभोग की आवश्यकता थी किंतु औपनिवेशिक सरकार ने 'स्वहितार्थ' वाणिज्यीकरण को नियंत्रित एवं अंततः आरोपित किया। इस प्रकार पूर्व काल में जहाँ कृषि अधिशेषों की बिक्री होती थी वहीं अब बिक्री हेतु उत्पादन होने लगा। भारत में इस नियंत्रित वाणिज्यीकरण की औपनिवेशिक नीति के प्रतिकूल प्रभाव हुए।

अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को कई कारणों से बढ़ावा दिया। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण जोरों पर था अतः वहाँ कच्चे माल की आवश्यकता थी। अतः ऐसी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जो ब्रिटिश उद्योगों एवं मजदूरों के खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

अंग्रेजों द्वारा शुरू की गयी नई लगान नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी इसीलिए किसान उन फसलों को उगाने के लिए मजबूर होने लगे जिसका बाजार में क्रय-विक्रय हो सके।

1853 के बाद ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा संचित पूंजी के निवेश की चिंता ने भारत में वाणिज्यिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया।

कम्पनी का चीन के साथ व्यापार के सन्दर्भ में व्यापारिक संतुलन चीन के पक्ष में था। इसके समाधान के तौर पर उसने भारत में चाय की खेती पर बल दिया ताकि चीन से होनेवाले चाय के आयात को कम किया जा सके। इसी प्रकार भारत से अफीम निर्यात के द्वारा व्यापारिक संतुलन लाने की कोशिश की गयी।

कपास, चाय, कॉफी, अफीम, नील, जूट आदि

Scanned with CamScanner

प्रमुख वाणिज्यिक फसलें थीं जिसे अंग्रेजों ने क्षेत्र विशेष के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बढ़ावा दिया था। जैसे - मद्रास में काली मिट्टी की उपलब्धता के कारण कपास की खेती पर बल, बंगाल में जूट उत्पादन, कर्नाटक में कॉफी, असम में चाय तथा अफीम के व्यापार हेतु पोस्त की खेती को बनारस, बिहार, बंगाल, मालवा में बढ़ावा दिया गया। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को अग्रिम धनराशि देने का प्रावधान किया, सिंचाई सुविधाएँ विस्तृत की तथा प्रतीम स्तर पर लोक-निर्माण विभाग की स्थापना की। कृषि उत्पाद पर निर्यात शुल्क को कम रखा गया। 19वीं सदी के द्वितीयार्द्ध में रेलवे की स्थापना से इस प्रक्रिया को काफी बल मिला। भारत में रेलों का जाल इस प्रकार बिछाया गया कि सुदूरवर्ती ग्रामीण उत्पादक क्षेत्र नजदीकी निर्यात केन्द्रों तथा बंदरगाह से जुड़ जाये।

इस प्रकार कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में एक स्वतंत्र प्रक्रिया न होकर नियंत्रित प्रक्रिया थी जिसमें कम्पनी सरकार ने स्वहितार्थ रुचि ली। यह मात्र राजस्व दबावों एवं शहरी आवश्यकताओं के मद्देनजर विकसित नहीं हो रहा था बल्कि निर्यात का तत्व इससे जुड़ा था।

ऐसे में नियंत्रित वाणिज्यीकरण की नीति ने भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। यह निर्यातोन्मुख था और चूंकि इन निर्यातों के बदले भारत को कोई आयात प्राप्त नहीं हो रहा था, इसीलिए इससे 'धन के अपवाह' (Drain of Wealth) की प्रक्रिया जुड़ गई।

वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असंतोष का संकट पैदा किया। भारतीय कृषि जगत एवं इससे जुड़ा समस्त तंत्र पूंजीवादी अर्थनीति के विश्वव्यापी तंत्र के एक पुर्जे के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार भारतीय कृषक को एक दूरस्थ एवं अपरिचित विदेशी बाजार पर आश्रित बना दिया गया जिसके साथ उसका एकमात्र संबंध बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला के माध्यम से था। ये बिचौलिए अपने मुनाफे के लिए किसानों का जमकर शोषण करते थे। मूल्यों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का भार भी अंततः किसानों को वहन करना पड़ता था। दरअसल भारतीय कृषक प्राकृतिक आपदाओं के अलावे - महाजन, अधिकारी एवं व्यापारी वर्ग की तिकड़ी द्वारा जकड़.

Scanned with CamScanner

लिया गया। नवीन तथा विशिष्ट उत्पादों की अधिकाधिक पूर्ति हेतु अधिक विनियोग की आवश्यकता ने उसे ऋण लेने को विवश किया। यही नहीं गरीब कृषकों ने जिन्होंने अपनी समस्त जमीन पर नकदी फसल उपजाए उन्होंने उपभोग-ऋण भी लिया जो इसेथा दोगुनी-तिगुनी ब्याज दरों पर मिलता। कृषक इस प्रक्रिया में पिसता हुआ दरिद्र होता गया किंतु उसके पास इससे निकलने का कोई चारा न था। समस्त मशीनरी उसके दमन हेतु तैयार थी। कृषकों को मजबूरन वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया से जुड़ना पड़ता था चाहे वह ऋण का भार हो या लगान चुकाने की मजबूरी। कोयम्बटूर के किसान ने शिकायत की थी कि वे कपास की खेती केवल इस कारण से करते हैं कि वे कपास खा नहीं सकते। अन्न तो खाने पर समाप्त हो जाता, परंतु कपास उगाने पर आधे पेट रहने पर भी लगान तो चुक जाता है। इस प्रकार अधिकांश कृषकों के लिए यह प्रकार का आरोपित वाणिज्यीकरण ही था, स्वैच्छिक या स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। इंग्लैंड के कृषकों के विपरीत इसका समस्त लाभ किसानों के बजाये ब्रिटिश सरकार को मिला।

कृषि के वाणिज्यीकरण में फसलें प्रायः औद्योगिक आवश्यकताओं (ब्रिटेन) को ध्यान में रखकर उगाई जाती थी फलतः खाद्यान्नों के बजाये नकदी फसलों की खेती ने अकाल एवं दुर्भिक्ष को आमंत्रित किया जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्राक्-ब्रिटिश काल में पड़नेवाले अकालों की मुख्य वजह प्राकृतिक तथा यातायात के साधनों का अभाव था किंतु ब्रिटिश काल में इसके पीछे औपनिवेशिक शोषणपूर्ण नीतियाँ काम कर रही थी।

चाय, नील जैसे नकदी फसलों का नियंत्रण यूरोपीय बगान मालिकों के हाथ में था। इसमें श्रमिकों की भर्ती दूर-दराज के क्षेत्रों से अनुबंध पद्धति के द्वारा की जाती थी जिसमें उनकी स्थिति दासों के समान हो गई।

वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया का सारा लाभ बिचौलियों को मिला या फिर उन किसानों को जो समृद्ध थे। इससे सामाजिक संरचना में असमानता की खाई चौड़ी हुई। जिनकी कीमत पर वाणिज्यीकरण हुआ वे अंततः दरिद्र ही बने रहे।

कृषि के वाणिज्यीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इसने 'आंचलिक विशिष्टीकरण' को जन्म दिया। विशेष क्षेत्र में विशेष फसल उत्पादन से विशेषीकृत क्षेत्र का विकास हुआ।

Scanned with CamScanner

कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ। इसके प्रभाव से उच्चतरीय सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं का विकास हुआ।

वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई। विभिन्न क्षेत्रों का आपसी जुड़ाव हुआ, ग्रामीण-शहरी सम्पर्क बढ़ा, अर्थव्यवस्था एकीकृत हुई। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का आधार तैयार किया।

ग्राम-नगर सम्बंध, वैश्वीकरण एवं पूँजीवाद के आरम्भ से अर्थव्यवस्था का मुद्राकरण हो गया जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आई।

वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग का शोषण हुआ पर यह समस्त प्रक्रिया भारत में राष्ट्रवाद के स्थान में सहायक सिद्ध हुई। किसानों ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठायी जिससे विभिन्न कृषक विद्रोह हुये। इससे भारतीय कृषक वर्ग के चुप होने की पारम्परिक अवधारणा टूटी।

कुल मिलाकर कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से परिचालित था फलतः इसका लाभ मुख्यतः अंग्रेजों को मिला। यह एक आरोपित प्रक्रिया थी जिसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। इसके कतिपय सकारात्मक प्रभाव ब्रिटिश नीतियों का हिस्सा नथा तथा यह लाभ भी धनि की तुलना में नगण्य था।

—x—

Scanned with CamScanner